जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर

Rashtradoot

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 33 संख्याः 68 प्रभात उदयपुर, गुरूवार 8 जनवरी, 2026 आर.जे. 7202 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

ट्रंप की ''ग्रीनलैंड'' पर आधिपत्य जमाने की धमकी से यूरोप में खलबली

वैनेज़ुएला पर सैनिक कार्यवाही के बाद, विश्व ट्रंप की ग्रीनलैंड की धमकी को केवल बड़बोलापन नहीं मान रहा। बल्कि, ट्रंप के गैर जिम्मेवारानापन व ''अनप्रैडिक्टिव सोच'' की निशानी मान रहा है

- ग्रीनलैंड, डेनमार्क के साम्राज्य का हिस्सा रहा है और डेनमार्क, नाटो का शुरु से सदस्य है, अब ''ग्रीनलैंड'' पर सैनिक कार्यवाही करना, नाटो के सदस्य के खिलाफ सैनिक आक्रमण है और नाटो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यूरोप में अमेरिका की मदद से खड़ा किया गया संगठन है, जिसने यूरोप में शांति और सुरक्षा बनाए रखी, रूस की तथाकथित आक्रामक सोच की छाया में।
- नाटो के अन्य सदस्यों, जैसे टर्की व स्कैण्डिनेवियन देशों ने अमेरिका की धमकी के खिलाफ आवाज़ उठाई है।
- इन देशों व अन्य यूरोपीय देशों का तर्क है, अमेरिका का हित नाटो सदस्यों में आपसी सहयोग बढ़ाने में है, न कि उन्हें आपस में लड़ा कर नाटो का विघटन करने में।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 जनवरी। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के इस बयान पर, कि ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए सैन्य बल ''हमेशा एक विकल्प'' है, डेनमार्क ने कड़ी राजनयिक प्रतिक्रिया दी है और नाटो में चिंता की लहर दौड़ गई है। हालांकि वॉशिंगटन का कहना है कि वह सिर्फ सभी विकल्प खुले रख रहा है। ये टिप्पणियां आर्कटिक द्वीप को अमेरिका के नियंत्रण में लाने की ट्रंप की लंबे समय से चली आ रही इच्छा की अब तक की सबसे आक्रामक अभिव्यक्ति हैं। यह बयान वैनेज़ुएला में हाल ही में हुए अमेरिकी सैन्य अभियान के बाद आया है, जिससे सहयोगी देशों में अमेरिका की अनिश्चितता को लेकर चिंता और बढ़ गई है।

वाइट हाउस ने ग्रीनलैंड को एक रणनीतिक संपत्ति बताया है, जिसकी अहमियत रूस और चीन के साथ आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण और बढ़ गई है। अधिकारियों का

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'मध्य प्रदेश के गाँवों में एक तिहाई पेयजल पीने योग्य नहीं है'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 जनवरी। मध्य प्रदेश के गांवों में, पेयजल चुपचाप सार्वजनिक स्वास्थ्य का हथियार बन गया है। केन्द्रीय सरकार के जल जीवन मिशन द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में एक तिहाई से अधिक पेयजल मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है, जिससे लाखों लोग अदृश्य, लेकिन जानलेवा प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं।

4 जनवरी 2026 को जारी की गई कार्यक्षमता आकलन रिपोर्ट (फंक्शनलिटी असेसमैंट रिपोर्ट) के अनुसार, मध्य प्रदेश में पानी के केवल 63.3 प्रतिशत नमूने गुणवत्ता परीक्षणों में पास हुए, जबकि राष्ट्रीय औसत 76

- केन्द्र सरकार की जल जीवन मिशन रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है और कहा गया है कि लाखों लोग भारी प्रदूषण का शिकार हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'चीन, रूस, क्यूबा और ईरान को बाहर निकालो'

ट्रंप ने वैनेज़ुएला की नई अंतरिम सरकार के लिए निर्देश जारी किए

- ट्रंप ने नई अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्ज़ से कहा कि चीन, रूस, ईरान व क्यूबा से कोई आर्थिक संबंध नहीं रखें।
- ट्रंप ने यह भी कहा कि तेल उत्पादन में सिर्फ अमेरिका के साथ भागीदारी की जाए और ''हैवी क्रूड'' सिर्फ अमेरिका को बेचा जाए।
- ट्रंप के इन दो टूक आदेशों से यह स्पष्ट है कि वैनेज़ुएला का प्रशासन एक तरह से वे ही चला रहे हैं।

- जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 जनवरी। बताया जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने वैनेज़ुएला के नए शासन, जिसे अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज़ के नेतृत्व में स्थापित किया गया है, से कहा है कि वे चीन, रूस, ईरान और क्यूबा को बाहर निकालें तथा इनके साथ आर्थिक संबंधों को ''तोड़ें'', ताकि उन्हें अधिक तेल उत्पादन करने की अनुमति दी जा सके। एबीसी न्यूज़ ने सूत्रों के हवाले से कहा है, ट्रंप प्रशासन चाहता है कि वैनेज़ुएला केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तेल उत्पादन में साझेदारी करे और भारी कच्चे तेल को बेचते समय अमेरिका को प्राथमिकता दे।

वैनेज़ुएला पिछले हफ्ते अमेरिकी हमलों के बाद, जब वैनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर बाहर भेज दिया गया था, राजनैतिक उथल-पुथल का सामना कर रहा है। इसके बाद, डेल्सी रोड्रिग्ज़ ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है, जबकि ट्रंप का कहना है कि वे अब इस दक्षिण अमेरिकी देश को नियंत्रित कर रहे हैं।

अब, एबीसी ने रिपोर्ट किया है कि ट्रंप प्रशासन ने वैनेज़ुएला के नए नेतृत्व से कहा है कि उन्हें अपने तेल भंडार से अधिक तेल निकालने की अनुमति तभी दी जायेगी, जब वे उनकी शर्तों का पालन करेंगे।

सूत्रों ने कहा, ''सबसे पहले तो, वैनेज़ुएला को चीन, रूस, ईरान और क्यूबा से सम्बंध खत्म करने होंगे और आर्थिक संबंधों को तोड़ना होगा। दूसरे, वैनेज़ुएला को केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तेल उत्पादन में साझेदारी करने पर सहमत होना होगा और हैवी क्रूड बेचते समय अमेरिका को प्राथमिकता देनी होगी।''

ज्ञातव्य है कि चीन लंबे समय से वैनेज़ुएला का करीबी साथी है और यह वैनेज़ुएला का सबसे बड़ा तेल खरीदार है।

'ऑपरेशन वैनेज़ुएला बहुत साफ-सुथरी व सर्जिकल सैनिक कार्यवाही थी'

पर, अब मालूम पड़ रहा है कि अमेरिका का यह दावा काफी थोथा व असत्य था, क्योंकि अब सब स्वीकार कर रहे हैं कि कम से कम 80 लोग मारे गए थे, कई सारे घर व मकान तहस-नहस हो गए थे, अमेरिकी बमबारी में

- जैसा कि अब अमेरिका ने भी स्वीकार किया है कि 150 अमेरिकी हवाई जहाजों ने आक्रमण में भाग लिया था, समुद्र के जहाजों, अन्य ट्रकों व टैंकों के अलावा। सभी को विशेषकर वैनेज़ुएला को आभास था कि अमेरिका आक्रमण करने वाला है तथा वैनेज़ुएला की आर्मी व वायु सेना तैयार थी लड़ाई के लिए। अतः आसमान में ''डॉग फाइट्स'' हुई व जमीन पर काफी गोलाबारी भी देखी गई थी।
- अमेरिका ने अब ''डिमांड'' रखी है, वैनेज़ुएला के समक्ष कि वह 50 मिलियन ऑयल दे, अमेरिका को, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बेचने के लिए तथा आमदनी अमेरिका के कोष में जमा होगी तथा थोड़ा बहुत अंश वैनेज़ुएला को भी मिलेगा।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 जनवरी। काराकस, वैनेज़ुएला में एक साफ़-सुथरा और सर्जिकल ऑपरेशन करने के अमेरिकी दावों के विपरीत, अब यह साफ हो गया है कि देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के अपहरण की पूरी कार्रवाई बेहद हिंसक और खून-खराबे वाली थी।

कम से कम 80 लोग मारे गए हैं। इनमें ड्यूटी पर तैनात वैनेज़ुएला और अन्य विदेशी भाड़े के सैनिकों के साथ-साथ वे आम नागरिक भी शामिल हैं, जो गोलीबारी की चपेट में आ गए। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं, क्योंकि सैन्य हमलों में उनके घर तबाह हो गए। वैनेज़ुएला के अधिकारियों को आशंका है कि मरने वालों की अंतिम संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है।

डॉनल्ड ट्रंप ने पूरे अभियान को बेहद हिंसक, लेकिन प्रभावी बताया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'गड़बड़ी सिद्ध हुए बिना पूरी भर्ती रद्द नहीं की जा सकती'

जयपुर, 7 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ में राज्य सरकार ने एसआई भर्ती-2021 भर्ती को एकलपीठ की ओर से रद्द करने को गलत बताया है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि यदि व्यक्तिगत स्तर पर गड़बड़ी हुई भी हो तो उसके चलते पूरे चयन तंत्र को दूषित मानकर भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार की ओर से बहस पूरी होने पर अदालत ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक टाल दी। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने ये आदेश राज्य सरकार व अन्य की अपील पर दिए।

- महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने एसआई भर्ती मामले में हाई कोर्ट में बहस पूरी की।

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वंशिका यादव के मामले में तय किया है कि जब तक किसी भर्ती में व्यापक और संगठित स्तर पर सिस्टमैटिक गड़बड़ी सिद्ध न हो तो

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका की आक्रामक वक्तव्यबाजी व हरकतों से ''अमेरिका विरोधी'' मंच तैयार हो गए हैं

यूरोप, चीन, टर्की के अलावा विश्व भर में लगभग सभी देश अमेरिका द्वारा वैनेज़ुएला में की गई सैन्य कार्यवाही के खिलाफ खुलकर मुखरित हुए हैं

- इस मुद्दे पर ऐसे-ऐसे देश भी एक मंच पर नज़र आए जो आपस में काफी कटुता पाले हुए हैं।
- सब का एक ही मत है कि ग्रीनलैंड के बाशिंदों को ही अन्ततोगत्वा अधिकार प्राप्त है कि वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं या किसी देश का आधिपत्य स्वीकार करना चाहते हैं।
- ग्रीनलैंड के निवासियों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में अपना निर्णय सुनाया है कि वे स्वाधीन रहना चाहते हैं, किसी अन्य देश में शामिल होकर अपना अस्तित्व नहीं खोना चाहते। अतः इन लोगों पर इस मुद्दे पर जोर-जबरदस्ती व दबाव डालना गैर-कानूनी व गैर वाजिब है।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 जनवरी। वैनेज़ुएला पर डॉनल्ड ट्रंप की कार्यवाही और टिप्पणी की वजह से उन देशों ने एक एंटी अमेरिकन मोर्चा बना लिया है, जो अब तक बिखरे हुए थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण एक बहुत ही चतुर और परोक्ष बयान वह है, जो प्रमुख यूरोपीय देशों ने ट्रंप के ग्रीनलैंड को ताकत से कब्जा करने की धमकी के खिलाफ दिया है।

ग्रीनलैंड पर ताकत से कब्ज़ा करना अब एक वास्तविक खतरा बन गया है, विशेष रूप से वैनेज़ुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अपहरण करने के बाद। इस कार्रवाई की दुनिया भर में, मित्र देशों और शत्रु देशों, दोनों द्वारा कड़ी निंदा की जा रही है।

अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक तनाव को और बढ़ाते हुए, डॉनल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी जानबूझकर ग्रीनलैंड पर अपना दावा दोहराकर अमेरिका के दखल देने की प्रवृति के खतरे को बढ़ा रहे हैं। इससे अमेरिका के नाटो सहयोगी गुस्से में हैं और सभी हैरान हैं।

यूरोपीय देशों ने स्पष्ट रूप से अपनी अस्वीकृति और निराशा व्यक्त की है, अमेरिका द्वारा देशों के बीच मुद्दों को सुलझाने के लिए कूटनीतिक व्यवहार के सभी मानदंडों की खुलकर निंदा भी की जा रही है। ग्रीनलैंड यूरोपीय महाद्वीप और अमेरिकी महाद्वीप के बीच स्थित है।

यूरोप ने विशेष रूप से कहा है कि ग्रीनलैंड वहाँ की जनता का है और किसी और देश का नहीं है और उसकी संप्रभुता और स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया है कि अगर अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े द्वीप पर हमला करने का प्रयास करता है तो क्या वे युद्ध में शामिल होंगे।

डॉनल्ड ट्रंप और उनके सहयोगियों ने बार-बार अमेरिकी राष्ट्रपति की इस बात को दोहराया है कि यह द्वीप स्वाभाविक रूप से अमेरिका का होना चाहिए। डॉनल्ड ट्रंप के एक प्रमुख सहयोगी की पत्नी ने ग्रीनलैंड का एक नक़्शा प्रकाशित किया था, जिसमें पूरे ग्रीनलैंड क्षेत्र पर अमेरिकी ध्वज लहराते हुए दिखाया गया था।

कुछ यूरोपीय देशों का कहना है कि डॉनल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड के बारे में बयान ''बेहद मूर्खतापूर्ण'' था।

डॉनल्ड ट्रंप ने बार-बार कहा है कि अमेरिका को अपनी सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात की ज़रा भी परवा नहीं की, वहां के लोगों ने स्पष्ट रूप से इस योजना का विरोध किया है। उनका कहना है कि ग्रीनलैंड को आत्मनिर्णय का अधिकार है, जैसे किसी अन्य देश को होता है।

वैनेज़ुएला पर अमेरिकी आक्रमण और राष्ट्रपति के अपहरण ने दुनिया भर में एंटी-अमेरिका मोर्चे को फिर से सक्रिय कर दिया है। इस कदम ने दुनिया के विभिन्न देशों को अमेरिका के खिलाफ कर दिया है और विभिन्न नेताओं ने इसके पड़ोसी देशों में अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की है।

तुर्की के राष्ट्रपति, रेसेप तईप एर्दोगान, ने अमेरिकी कार्रवाई की निंदा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

झारखंड में जंगली हाथी ने 7 को मारा

चाईबासा (पश्चिमी सिंहभूम), 07 जनवरी। नोवामुंडी प्रखंड के जेटेया थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबरिया गांव में 6 जनवरी की रात जंगली हाथी के हमले से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पति-पत्नी और उनके दो मासूम बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा दूसरे परिवार के एक सदस्य की भी हाथी के हमले में जान चली गई। घटना रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है।

- एक परिवार घर पर सो रहा था, जब हाथी ने अचानक हमला किया।

बताया गया कि सभी लोग अपने घर में सो रहे थे, तभी हाथी ने अचानक घर पर हमला कर दिया। इस दौरान परिवार का एक बच्चा किसी तरह जान बचाने में सफल रहा। बाबरिया गांव में मृतकों की पहचान सनातन मेराल, उनकी पत्नी जोंकों कुई, उनके दो मासूम बच्चों और मोगदा लागुरी (दूसरे परिवार से) के रूप में हुई है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप के ''वैनेज़ुएला एक्ट'' पर भारतीय प्रतिक्रिया के गहरे मायने हैं

भारत सरकार के कूटनीतिक बयान पर भारत में ही मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है

- कांग्रेस, वामपंथी दलों एवं राजद ने भारत सरकार की हल्की प्रतिक्रिया की कड़ी आलोचना की। कांग्रेस ने कहा, अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन पर भारत को कड़ा विरोध जताना चाहिए। राजद के मनोज झा ने कहा कि इस सतर्क भाषा के लिए इतिहास भारत को माफ नहीं करेगा। वामपंथी दलों ने भी भारतीय रूख की तीखी आलोचना की।
- लेकिन कांग्रेस के शशि थरुर ने अवश्य सरकार के रूख का बचाव किया और कहा कि भारत ना तो छोटा देश है ना ही कोई राजतंत्र और टूटते अंतर्राष्ट्रीय नियमों के इस दौर में भारत की प्रतिक्रिया लोक लुभावन भाषणों से नहीं बल्कि कूटनीति से प्रभावित होनी चाहिए।
- कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया कूटनीतिक विशेषज्ञ सुहासिनी हैदर ने दी,और कहा, जहाँ कहीं भी अमेरिका की भागीदारी होती है, उस पर हमारी प्रतिक्रिया बेहद सतर्क होती है। यह जरूरी भी है, क्योंकि इस समय भारत-अमेरिका ट्रेड डील संवेदनशील दौर से गुज़र रही है।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 जनवरी। अमेरिका द्वारा वेनेज़ुएला पर किए गए सैन्य हमले पर भारत की बेहद हल्की प्रतिक्रिया रही, जिसमें वॉशिंगटन की साफ निंदा करने के बजाय केवल शांति की अपील की गई है। इसे लेकर राजनीतिक विरोधियों, वाम दलों और विदेश नीति विशेषज्ञों ने कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि भारत ने संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानून के अपने पुराने सिद्धांतों के बजाय, अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक और आर्थिक रिश्तों को प्राथमिकता दी है। इसमें ऊर्जा आपूर्ति भी दांव पर है। भारत पूर्व में वेनेज़ुएला से कच्चे तेल का बड़ा खरीदार रहा है और 2024 की शुरुआत में, जब कुछ समय के लिए प्रतिबंधों में ढील दी गई थी, तब भारत रोज़ करीब 1.30 लाख बैरल तेल आयात करता था। वर्ष 2025 में यह घटकर बहुत कम रह गया और अमेरिकी प्रतिबंधों व अनुपालन के जोखिम के कारण लगभग बंद सा हो गया। हालांकि सरकार का कहना है कि 2025 में भारत के कुल कच्चे तेल आयात में वेनेज़ुएला की हिस्सेदारी केवल करीब 0.6 प्रतिशत थी। आलोचकों ने चेतावनी दी कि अमेरिका को खुलकर चुनौती न देने से भविष्य में वेनेज़ुएला से सस्ता क्रूड हासिल करना मुश्किल हो सकता है और बड़े पैमाने पर खरीद दोबारा शुरू करने पर वॉशिंगटन की ओर से दंडात्मक कार्रवाई का खतरा रहेगा।

कई देशों ने इस अमेरिकी कार्रवाई को एक संप्रभु देश पर एकतरफा सैन्य हमला बताते हुए खुली निंदा की, लेकिन भारत ने केवल बातचीत करने और स्थिरता बनाए रखने की सामान्य अपील तक खुद को सीमित रखा। वॉशिंगटन का नाम लेने या उसकी आलोचना करने से वह बचता रहा। इस तरह की चुप्पी से देश के भीतर राजनीतिक और बौद्धिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। आलोचकों का कहना है कि इससे वैश्विक दक्षिण की मुखर आवाज़ के रूप में भारत की साख कमज़ोर पड़ सकती है।

काराकस में अमेरिकी कार्रवाई के करीब 24 घंटे बाद विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर वेनेज़ुएला के लोगों की सुरक्षा और कल्याण के प्रति समर्थन जताया और सभी पक्षों से शांतिपूर्ण समाधान की अपील की। इस बयान में न तो अमेरिका का नाम था, न बमबारी और राष्ट्रपति मादुरो व उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी का ही कोई उल्लेख था। इससे एक दिन पहले भारत ने अपने नागरिकों को वेनेज़ुएला की गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी थी, जिसे व्यावहारिक कदम माना गया, लेकिन यह भी संकेत दिया गया कि भारत को पहले से हालात की जानकारी थी, फिर भी राजनीतिक रूप से स्पष्ट रुख नहीं अपनाया गया।

इस प्रतिक्रिया पर विपक्षी नेताओं ने तुरंत निशाना साधा। कांग्रेस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

संसद का सत्र 28 से संभव

नई दिल्ली, 07 जनवरी। केंद्र सरकार एक फरवरी को आम बजट पेश कर सकती है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की बुधवार को हुई बैठक में संसद के आगामी बजट सत्र की तारीखों का प्रस्ताव रखा गया।

राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने संसद के बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी से करने और 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करने का प्रस्ताव रखा है।

- एक फरवरी को केन्द्रीय बजट पेश होगा।

सूत्रों के अनुसार, इन तारीखों पर अभी अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है और जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है।

बजट सत्र दो हिस्सों में आयोजित किया जाता है। पहले और दूसरे हिस्से के बीच अवकाश रखा जाता है, ताकि संसदीय स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच कर सकें।